EDITORIAL

Reality in Dark

It is published in print media that BSNL/ MTNL are moving in positive direction in connection with their financial health. The news was flashed through press statement in January, 2021 by the Department of Telecom. The news gives a very encouraging message to the working employees of BSNL, who are suffering a lot due to curtailment of their several welfare and protective measures. Even they are waiting from long time for their carrier progression. So far financial position of BSNL has been defined in the press release that the company has turned towards operational Profit in comparison to year 2020. The common workers are unable to understand the statement whether the company is in operational profit or not, because they are not getting their salary on time from last one and half year. Now, there is no fixed date for the payment of salary for BSNL employees. In this situation, the very impressive press statement regarding improvement of financial health of BSNL has not bring the happiness among the employees and adverse comments coming on reality of the statement.

After the revival package announced by our Hon'ble Communications Minister, no progress is seen on ground level. Maintenance of services has been handed over to so called out sourced agencies, which resulting huge disconnections of landlines, Broadband connections and other services in the field.

Almost all contract Labourers have been retrenched without paying their wages for last two years. The vendors are not taking their services, because they have to hide the actual figure of the labourers working in the field. The regular left out employees after VRS are living in much suffocation. Neither promotional departmental examinations are taking place nor the new promotion policy is under consideration. The Junior Engineers are waiting for the LICE of JTO even after completion of 7 years/ 8 years of their services. Similar is the position of TT and ATT.

Democratic and transparent discussions/decision and open chance to all to raise their grievances has became a past history.

In the situation the trade union has to fulfil its task to ensure notification of promotional examination, restoration of frozen IDA w.e.f. 01-10-2020. Payment of pending medical bills and TA bills. Demand of 3rd wage revision is still pinching the heart of the workers and they are knocking the door of union. All together we have to do a lot for the workers in the year 2021.

To complete our task, unity inside of our own union and broader unity of all unions/associations is need of the hour.

The NFTE is always in favour of unity and raised its voice to bring all the union/associations under one umbrella with a common minimum demands of the workers and issues related to survival of BSNL company should be ensured to organise strong struggle. The NFTE will play the role of vanguard as its policy and tradition.

National Executive Committee Meeting will be held on 13th & 14th March, 2021 at Nagpur (Maharashtra)

संपादकीय

वास्तविकता अंधकार में

नव वर्ष के प्रथम माह जनवरी के पूर्वाद्ध में समाचार पत्रों में दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। उक्त स्टेटमेंट में यह दर्शाया गया है, कि बीएसएनल एवं एमटीएनएल इस वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में 2020 की इसी अवधि की तुलना में आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर है और यह भी बताया गया है कि कम्पनी संचालन लाभ में पहुंच गई है इस आशय के साथ ही यह भी घोषित किया गया है कि अगले वर्षों में कंपनी पूर्ण लाभ की स्थिति प्राप्त कर लेगी। आम कार्यरत कर्मचारी इन समाचारों को पढ़कर उलझन में पड़ जाते हैं। हालांकि ये समाचार कर्मचारियों के लिए उत्साहवर्धक है परंतु कर्मचारी ऐसे समाचारों से अब बिल्कुल अविश्वास करने लगे हैं।

ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2020 में माननीय संचारमंत्री भारत सरकार ने भारत सरकार की मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पुनः उत्थान पैकेज की घोषणा की थी, जिस पर केंद्र सरकार सत्तर हजार रूपये खर्च करने की बात कहीं गई थी। उस पैकेज में बी.आर.एस. को छोड़कर कुछ भी सरजमीन पर नहीं आया लगभग आधे से अधिक कर्मचारी और अधिकारी वी.आर.एस. के माध्यम से कंपनी से बाहर कर दिये गये, बावजूद इसके जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहे हैं। अब बीएसएनएल में कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं है। प्रबंधन जब चाहे वेतन का भुगतान कर सकती है। बिना ठोस कार्य योजना निर्धारण के बी.आर.एस. किया गया और उसके बाद कंपनी की सेवाओं का रखरखाव तथाकथित आउटसोर्सिंग से की जा रही है। सभी पुराने ठेका मजदूरों को उनके दो वर्ष के बकाये मजदूरों का भुगतान किये बगैर कंपनी से बाहर कर दिया गया। नये वेंडर पुराने कामगारों को रखना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें कार्य पर लगाये गये फर्जी मजदूरों की मजदूरी पचाने में व्यवधान हो सकता है। बाह्य एजेंसी सेवाओं के रखरखाव ऐसे करती है कि तमाम जगहों पर लैंडलाइन, ब्राडबैंड एवं अन्य सेवा को उपभोक्ता वापस कर रहे हैं। पूरी अराजक स्थिति है तथा प्रबंधन अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ चौन की बंशी बजा रही है।

कर्मचारी हत् प्रभ हैं। उनको प्राप्त होने वाली कई कल्याण ाकारी सुविधाओं को विरमित कर दिया गया है। उनके लम्बित एवं ज्वलंत मांगों की अनुसुनी की जा रही है।

कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा यात्रा भत्ता सुविधा से तो वंचित किया गया था अभी जले पर नमक छिड़कने की कहावत को चरितार्थ करते हुए उनके महंगाई भत्ते को भी बंद कर दिया गया है, जबकि भारत सरकार के उपक्रम विभाग ने लिखित रूप से कोयला एवं खनिज सम्पदा विभाग को स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को बंद करने का आदेश नॉन–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर लागू नहीं है। हमारे कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के संज्ञान में इन तथ्यों के लाने के उपरांत भी इस पर ध्यान दे देना उन्होंने उचित नहीं समझा। कंपनी में बचे कार्यरत कर्मचारियों के चेहरे से मुस्कान विलोपित हो चुका है। कर्मचारियों के लिए ना तो पदोन्नति की परीक्षा आयोजित की जा रही है और ना ही उनके लिए नयी पदोन्नति नीति पर विचार किए जा रहे हैं। विभागीय परीक्षाएं कई वर्षों से लंबित हैं। उच्च योग्यता धारी कनीय अभियंता 7–8 वर्ष की सेवापूर्ण कर चुके हैं पर उनके लिए जे.टी.ओ. की परीक्षाएं नहीं हो रही है, जबकि पांच वर्ष की सेवा अवधि ही परीक्षा के लिए वांछित है। इसी प्रकार से ए.टी.टी. से टी.टी. एवं टी.टी. से जे.ई. की परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की जा रही हैं। पीड़ादायक स्थिति तो यह है कि दो वर्ष पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से टी.टी. संवर्ग में प्रोन्नति हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

अर्हता प्राप्त कर्मचारियों ने आवेदन किया उनसे 400 रूपये प्रति परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क भी लिया गया परन्तु परीक्षा दो वर्ष बीत जाने के बावजूद आयोजित नहीं की जा सकी है। इस भयावह स्थिति से बुरा और क्या हो सकता है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 एवं 14 मार्च 2021 नागपुर में होगी